आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नागपुर

बनाम

मेसुर्स वेंगंगा सहकारी समिति कारखाना लिमिटेड

अप्रैल 18,2002

[मुख्य न्यायाधिपति एस. पी. भरुचा, न्यायाधिपति एन. संतोष हेगड़े और न्यायाधिपति शिवराज वी. पाटिल]

आबकारी कानूनः पुलिंदा, स्तम्भ और पर्लाइन-बनाना-क्या इसके बराबर है निर्माण-धारण, ट्रिब्यूनल ने नोट किया कि यह कलेक्टर द्वारा एक तथ्य के रूप में पाया गया था कि निर्धारिती ने साइट पर निर्माण कार्य किया था - अरुणा इंडस्ट्रीज मामले का निर्णय तत्काल मामले पर लागू किया गया - ट्रिब्यूनल के आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता

अरुणा इंडस्ट्रीज विशाखापट्टनम बनाम सी सी ई गुंटूर, (1986) 25 ईएलटी 580, पर भरोसा किया।

संरचना और मशीनरी (बोकारो) प्राइवेट लिमिटेड बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (1984) (17) ई एल टी 127 और रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड बनाम कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (1988) 38 ई एल टी 176 का उल्लेख किया गया है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 496 /1998

सीमा शुल्क उत्पाद एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली के ए नं. ई/739/89-बीएल में एफ.ओ. नं. ई/866/97-बी के निर्णय एवं आदेश दिनांक 7.5.97 से

मुकुल रस्तोगी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, जयदीप गुप्ता और बी. के. प्रसाद अपीलार्थी के लिए।

वी. लक्ष्मीकुमारन, एम. पी. देवनाथ और वी. बालचंद्रन प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था

न्यायाधिकरण इस बात से चिंतित था कि क्या पुलिंदा, स्तम्भ और पर्लाइन बनाना विनिर्माण के बराबर है। न्यायाधिकरण ने अरुणा इंडस्ट्रीज, विशाखापत्तनम बनाम सी.सी.ई गुंटूर {1986) 25 ईएलटी 580 के मामले में पहले के फैसले का पालन किया। इसने स्ट्रक्चरल्सएंडमशीनरीज (बोकारो) प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टर (1984)17 ईएलटी 127 के मामले में एक अन्य फैसले का पालन नहीं किया। .

राजस्व की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि न्यायाधिकरण द्वारा परस्पर विरोधी विचार रखे गए हैं और विवादित आदेश के बाद भी ऐसे विरोधाभासी विचार लिए गए हैं।

इन बाद के निर्णयों में से एक में, रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, (1988] 38 ईएलटी 176 के मामले में, अरुणा इंडस्ट्रीज (सुप्रा) के मामले पर विचार किया गया है

और ऐसी स्थितियों पर लागू पाया गया है जहां निर्धारिती निर्माण स्थल पर संरचनाएं खड़ी कर रहा था और मौके पर सामग्री का निर्माण कर रहा था; इसलिए यह पाया गया कि इसे किसी कारखाने में निर्माण नहीं माना जा सकता है। अब, तत्काल मामले में, ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह एक तथ्य के रूप में पाया गया था कलेक्टर द्वारा कि निर्धारिती ने साइट पर निर्माण कार्य किया था। इसलिए, यह एक ऐसा मामला था, जिसमें अरुणा इंडस्ट्रीज (सुप्रा) का निर्णय लागू होता था और ट्रिब्यूनल के आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता था।

अपील खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

आर पी

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।